बंजर-भूमि विकास बोर्ड के स्थान पर तकनीकी मिशन की स्थापना

171. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में बंजर भूमि विकास बोर्ड के स्थान पर तकनीकी मिशन की स्थापना कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तथा बोर्ड की स्थापना के विशिष्ट लक्ष्य क्या थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बोर्ड अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत नये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सरकार ने परती भूमि विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और उसका स्तर बढ़ाने के लिए 5 अक्तूबर, 1989 को परती भूमि विकास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया है । राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड अभी विद्यमान है ।

(ख) से (ङ) वर्गीकरण और वृक्षारोपण के व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से देश में परती भूमि विकास आरंभ करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर 7 मई, 1985 को राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड (रा० प० भूमि बोर्ड) की स्थापना की गई थी । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण के वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	लक्ष्य (मि०है० में)	उपलब्धियां (मि० है० में)
1985–86	1.45	1.51
1986–87	1.71	1.76
1987–88	1.79	1.77
1988–89	2.00	2.12
1989–90	1.70	––

वर्ष 1989-90 के लक्ष्यों को इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त किए जाने की आशा है ।

बोफोर्स तोप-सौदा

172. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 दिसम्बर, 1989 के "हिन्दू" दैनिक में "बोफोर्स" क्विक स्विस रेसपोंस लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोफोर्स तोप-सौदे में दी गई दलाली के संबंध में इस मामले में अगली कार्यवाही के संबंध में कोई योजनाएं बनाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भजे गए अनुरोध-पत्र का स्वीडन सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तेजी से जांच करने के लिए कहा गया है ।

आम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि

173. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में आम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मूल्य-वृद्धि को रोकने तथा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता-वस्तुओं को आसानी से सुलभ कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इस समय बेची जा रही